भा.क.नि
CCI

भारतीय कपास निगम लिमिटेड,

(भारत सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय, कपास भवन, प्लॉट नं.3/ए, सेक्टर-10, सीबीडी बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614, फैक्स नं. 27576030, 27579219, 27576069,
टेली.नं. 27579217, ई-मेल/E-mail: headoffice@cotcorp.com

प्रेस विज्ञप्ति

सीसीआई द्वारा 89.4 लाख गाँठों की अब तक की सर्वाधिक रिकार्ड खरीद.

सीसीआई के कार्य-निष्पादन की संक्षिप्त विशिष्टाएँ

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की 29 अगस्त, 2009 को मुंबई में आयोजित 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक.

विश्वीय आर्थिक मंदी और प्रतिकूल कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण कपास मौसम 2008-09 पुन: एक बार चुनौती का वर्ष रहा है । निगम ने सौंपी गई भूमिका के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य संचालन द्वारा देश के कपास किसानों की सहायता करने और कताई क्षेत्र में उपभोक्ता मिलों को गुणवत्तावाली कपास की आपूर्ति करने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है ।

वर्ष 2008-09 में कपास के अधीन क्षेत्र में लगभग 1% की गिरावट :

वर्ष 2008-09 में कपास के अधीन क्षेत्र पिछले वर्ष के 94.4 लाख हेक्टर की तुलना में 1% गिरावट के साथ 93.7 लाख हेक्टर्स पर पहुँच गया है, जो प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियों, कीट और बॉलवार्म की घटनाओं, नहर के जल को न छोड़ने से जल की अत्यधिक कमी, वर्षा ऋतु में देर आदि के कारण हुआ ।

विश्व में दूसरे बड़े कपास उत्पादक के रूप में भारत ने अपनी स्थिति बनाये रखी :

वर्ष 2008-09 में प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियों के बावजूद बीटी उपज की आकस्मिक वृद्धि के साथ, देश में कपास उत्पादन पिछले वर्ष की 315 लाख गाँठों की तुलना में 290 लाख गाँठें हुआ । इस प्रकार भारत ने विश्व में चीन के बाद दूसरे बड़े कपास उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बनाये रखी ।

कपास उत्पादकता गिरी :

देश में कपास उत्पादकता, जो पिछले कुछ वर्षो से लगातार बढ़ रही थी, पिछले वर्ष के 567 किग्रा. प्रति हेक्टर्स के स्तर से गिरकर वर्ष 2008-09 में 526 किग्रा. प्रति हेक्टर्स हो गयी ।

<u>न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन में वृद्धि :</u>

वर्ष 2008-09 में भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन में उल्लेखनीय वृद्धि दी है । मध्यम तंतु के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1800/- रूपये प्रति क्विंटल के स्तर से 2500/- रूपये प्रति क्विंटल तक लगभग 39% की वृद्धि हुई, जबकि लंबे तंतु के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष के 2030/- रूपये प्रति क्विंटल के स्तर से 3000/- रूपये प्रति क्विंटल तक लगभग 49% की वृद्धि की गयी ।

<u>देश से कपास निर्यात :</u>

वर्ष 2008-09 के दौरान भारत सरकार की विशेष कृषि ग्राम उपज योजना के अंतर्गत डयूटी क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन योजना और देश में कपास की अत्यधिक उपलब्धता के बावजूद देश से कपास निर्यात देशी मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में विसंगति के कारण बढ़ नहीं सका है। इसके परिणामस्वरूप सीएबी द्वारा 50 लाख गाँठों के अनुमानित कपास निर्यात के विरूद्ध 13 अगस्त, 2009 को निर्यात के लिए लगभग 33 लाख गाँठें पंजीकृत की गई, जिनमें से 28 लाख गाँठों के पोतवहन होने की सूचना है ।

<u>कपास का आयात :</u>

पिछले वर्ष की तरह देश में कपास आयात पुन: एक बार अतिरिक्त लंबे तंतु की कपास की कम आपूर्ति तक लगभग 7.00 लाख गाँठों तक सीमित रहा है, जिसमें मिलों द्वारा संविदागत लगभग 2 लाख गाँठों की लंबे तंतु की किस्मों का आयात शामिल है 1

<u>सीसीआई का रिकार्ड न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य संचालन</u>

पिछले कुछ वर्षो से सीसीआई लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य संचालन कर रहा है । कपास मौसम 2008-09 के दौरान सीसीआई ने सभी कपास उत्पादक राज्यों में प्राय: संपूर्ण मौसम में रिकार्ड न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य संचालन किया है और 89.4 लाख गाँठों के समकक्ष 450 लाख क्विंटल कपास की रिकार्ड मात्रा खरीदी है । ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य वर्ष 2004-05 में 27.5 लाख गाँठों की इस प्रकार की खरीद से तीन गुना अधिक है ।

<u>4972 करोड़ रूपये का रिकार्ड बिक्री टर्न-ओवर :</u>

आलोच्य वर्ष के दौरान देशी मिलों को आयात पर निर्भर होने के स्थान पर उचित मूल्यों पर कपास उपलब्ध कराने में सहायता देने के उद्देश्य से व्यावहारिक बिक्री नीति के साथ-साथ बिक्री से पहले और बिक्री के बाद की बेहतर सेवाएँ देते हुए, निगम ने पिछले वर्ष के 1637 करोड़ रूपये के टर्न-ओवर की तुलना में इस वर्ष 4972 करोड़ रूपये का रिकार्ड टर्न-ओवर प्राप्त किया है । यह रिकार्ड टर्न-ओवर निगम द्वारा वस्त्र मंत्रालय के निदेशों के अनुसार फरवरी, 2000 में आरंभ की गई बड़ी मात्रा में खरीद पर छूट योजना के प्रति देशी मिलों/ व्यापारियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारण प्राप्त हुआ है ।

<u>वर्ष 2008-09 में सीसीआई की लाभप्रदता :</u>

वर्ष 2008-09 में निगम ने गत वर्ष के 22.55 करोड़ रूपये (कर के बाद) लाभ के विरूद्ध 66.78 करोड़ रूपये (कर के बाद) का शुद्ध लाभ अर्जित किया है । लाभ में यह वृद्धि मुख्यत:, वर्तमान वर्ष

में पिछले वर्ष के 4.81 लाख गाँठों के आगे लाये गये स्टॉक की बिक्री और इस प्रकार के स्टॉक पर अर्जित रख-रखाव प्रभार, किराये पर आय, निगम की निधियों पर अर्जित आय, अशोध्य ऋण की वसूली के कारण है ।

भारत सरकार को लाभांश का लगातार भुगतान :

लगातार अच्छे कार्य-निष्पादन को देखते हुए निगम ने कर के बाद लाभ पर 20% के लाभांश की घोषणा की है, जो 15.7 करोड़ रूपये (लाभांश पर कर सहित) बनता है जबकि पिछले वर्ष 5.85 करोड़ रूपये (लाभांश पर कर सहित) रहा है ।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) का कार्यान्वयन :

फरवरी, 2000 में 11वीं योजना के अधीन 3 वर्षो के लिए आरंभ किए गए कपास प्रौद्योगिकी मिशन का आरंभ में 10वीं योजना की अवधि के लिए विस्तार किया गया और आगे इसे मार्च, 2010 तक विस्तार दिया गया है । मिनी मिशन-III के अधीन 250 मार्केट यार्डस के प्रस्तावों को विकास के लिए मंजूरी दी गई, जिनमें से 178 एपीएमसी पूर्ण होने की सूचना है । 250 मार्केट यार्डस के लिए कुल परिव्यय 489.27 करोड़ रूपये है, जिसमें टीएमसी की सहायता 253.38 करोड़ रूपये है । इन मार्केट यार्ड के विकास ने कपास में संदूषण को न्यूनतम करने में सहायता दी है, ताकि कपास किसानों को उनकी कपास के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके । इसी प्रकार मिनी मिशन-IV के अधीन आधुनिकीकरण के लिए 1000 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के लक्ष्य में से 1013 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 857 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के पूर्ण होने की सूचना है । निगम कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-III तथा IV के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करता रहा । जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए कुल परिव्यय 1432.05 करोड़ रूपये है, जिसमें टीएमसी की सहायता 224.79 करोड़ रूपये है । जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण ने ट्रैश /संदूषण स्तर घटाया है और संसाधन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया है ।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन इन प्रयत्नों ने देशी वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समकक्ष बेहतर संसाधित संदूषण मुक्त कपास प्राप्त करने में सहायता दी है । भारतीय कपास अब अन्य निर्यातक देशों की कपास के समकक्ष मानी जाती है ।

मिनी मिशन-II के अधीन फ्रंट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन :

निगम ने नोडल एजेन्सी के रूप में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अधीन फ्रंट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यान्वयन उत्पादन प्रौद्योगिकी पर 4400 से अधिक एफएलडी और आईपीएम प्रौद्योगिकी 2 एफएलडी का आयोजन सभी मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में सीसीआई की प्राय: सभी शाखाओं की सहभागिता से किया है ।

सघनित कपास खेती (संविदा खेती) :

वर्ष 2008-09 के दौरान निगम सघनित कपास खेती की संकल्पना को प्रोत्साहित और लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न करता रहा है और इस कार्यक्रम का विस्तार अपनी शाखाओं के माध्यम से 46,837 हेक्टर्स क्षेत्र में प्राय: सभी कपास उत्पादक राज्यों में किया है ।

****

भा.क.नि.
CCI
भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम /A Government of India Undertaking)
प्रशासकीय एवम पंजीकृत कार्यालय: कपास भवन, प्लॉट नं.३-ए, सेक्टर १०, सीबीडी, बेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६१४
Admn & Regd. Office: Kapas Bhavan, Plot No.3-A, Sector 10, CBD, Belapur, NAVI MUMBAI 400 614
दूरभाष/Phone:27579217,फैक्स/Fax:27576030/27579219,ई-मेल/email:headoffice@cotcorp.com,वेबसाईट/website: www.cotcorp.gov.in

PRESS RELEASE

RECORD HIGHEST-EVER PURCHASES OF 89.4 LAKH BALES BY CCI

BRIEF HIGHLIGHTS OF CCI'S PERFORAMNCE

39TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD (CCI) HELD ON 29TH AUGUST 2009 IN MUMBAI.

The cotton season 2008-09 had once again been a year of challenge due to global economic melt down and adverse agro-climatic conditions. The Corporation, as per the role assigned, had successfully come out to fulfill its objective of helping the cotton farmers of the country through record MSP operations and of supplying quality cotton to user mills in the spinning sector.

Acreage under cotton during 2008-09 decreased by around 1%

The acreage under cotton during 2008-09 had decreased by 1% at 93.7 lakh hectares as against 94.4 lakh hectares during the previous year due to adverse agro-climatic conditions as compared to previous year, incidences of pests and bollworms, acute shortage of water due to non-release of canal water, delayed monsoon rains etc.,.

India retained the position as the second highest cotton producer in world

Despite adverse agro-climatic conditions during 2008-09, with advent of increased Bt cultivation, cotton production in the country had been at 290 lakh bales as against 315 lakh bales during the previous year. Thus, India has retained its position as the second highest cotton producing country in the world, after China.

Cotton productivity declined

Cotton productivity in the country, which was continuously rising over the years, has decreased to 526 kgs per hectare in 2008-09 from the level of 567 kgs per hectare in last year.

Significant increase in MSPs

During 2008-09, the Government of India had given substantial rise in the Minimum Support Prices (MSPs). The MSP for medium staple has been

increased by around 39% to Rs.2500 per quintal from the level of Rs.1800 per quintal, whereas the MSP for long staple had been increased by around 49% at Rs.3000/- per quintal from the level of Rs.2030 per quintal last year.

Cotton exports from the country

Despite Incentive Scheme of the Government of India in the form of duty credit scrip under Vishesh Krishi Gram Upaj Yojna (VKGUY) and abundant availability of cotton in the country during 2008-09, cotton exports from the country could not pick up due to disparity in domestic prices vis-à-vis international cotton prices. As a result, as against estimated cotton exports of 50 lakh bales by CAB, as on 13th August 2009, around 33 lakh bales have been registered for exports out of which around 28 lakh bales have been reported shipped.

Imports of cotton

Like previous year, cotton imports into the country were once again limited to short supply in Extra Long staple cottons at around 7.00 lakh bales inclusive of import of around 2 lakh bales of long staple varieties contracted by mills.

Record MSP operations of CCI

Over the years, CCI has been continuously undertaking MSP operations. During cotton season 2008-09, CCI had undertaken record MSP operations almost throughout the cotton season in all the cotton growing States and had purchased record quantity of 450 lakh quintals of kapas equivalent to 89.4 lakh bales. These MSP operations were more than three times than last such purchases of 27.5 lakh bales in 2004-05.

Record sales turn-over of Rs.4972 crores

During the year under review, with pragmatic sales policy aimed at enabling the domestic mills to source cotton at reasonable prices, rather than depending on imports, better pre-and-post sales services, the Corporation has achieved a record sales turn-over of Rs.4972 crores as against turnover of Rs.1637 crores during the previous year. The record turn-over has been due to encouraging response from the domestic mills/traders to the Bulk Quantity Discount Scheme introduced by the Corporation in February 2009 as per the directives from the Ministry of Textiles.

Profitability of CCI in 2008-09

During the financial year 2008-09, the Corporation has earned a net profit of Rs.66.78 crores (after tax) as against profit of Rs.22.55 crores (after tax) during the previous year. The increase in profit has been mainly due to disposal of commercially purchased carried forward stock of 4.81 lakh bales sold in the current year and carrying charges earned on such stocks, rental income, interest earned on Corporation's funds and bad debts recovery.

Continued payment of Dividend to Government of India

In view of its continued good performance, the Corporation has declared dividend @ 20% on post tax profit aggregating to Rs.15.7 crores (including

tax on dividend) as against Rs.5.85 crores (including tax on dividend) during the last year.

Implementation of Technology Mission on Cotton (TMC)

The Technology Mission on Cotton, which was launched in February 2000 for three years under IXth Plan period, was initially extended for Xth Plan period and the same was further extended upto March 2010. Under Mini Mission-III proposals for 250 market yards had been sanctioned for development out of which 178 APMCs have reported completion. Total outlay for 250 market yards had been Rs.489.27 crores with TMC assistance of Rs.253.38 crores. The development of these market yards has helped in minimizing the contamination in kapas so as to enable the cotton growers to get better price for their cotton. Similarly, out of target of 1000 G&P units for modernization under MM-IV, 1013 proposals had been approved out of which 857 G&P units have reported completion. Corporation continued to be the implementing agency for Mini Mission III and IV of the Technology Mission on Cotton. The total outlay for modernization of these G&P units had been Rs.1432.05 crores with TMC assistance of Rs.224.79 crores. Modernization of G&P factories has reduced trash/contamination levels and has also improved the overall quality of processing.

These efforts under TMC have enabled the domestic textile industry to get better processed and contamination free cotton at par with international standards. Indian cottons are now accepted at par with cotton of other exporting countries.

Front Line Demonstrations under Mini Mission II

As the nodal agency for implementing Front Line Demonstrations under Mini Mission II of the Technology Mission on Cotton, the Corporation has successfully organized more than 4400 FLDs on Production Technology and 2 FLDs on IPM Technology in all major cotton growing States by associating almost all CCI branches.

Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming)

Corporation continued its efforts to promote and popularize the concept of Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming) during 2008-09 and had extended the programme in almost all the cotton growing States in an area of 46,837 hectares through its Branches.

---oo00oo---